'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 31 अक्टूबर, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 23 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 अक्टूबर, 2013

एक सद्गुणी व्यक्ति तृष्णावश, क्रोध, अज्ञान या भय से भ्रमित नहीं होता।

—गौतम बुद्ध

हमारा जुर्म

डॉ. उदित राज

हम भावना एवं सपना दोनों से दूर रहे। बहुतों को यह बात समझ में आई नहीं। हमारा देश भावनाओं का है शायद इसका एहसास हमें नहीं हो पाता। हमारी जमात पढ़े–लिखे लोगों की है जो तर्कसंगत और व्यवहारिक है। यह भी बहुत सच है कि इन पढ़े–लिखे लोगों का नेतृत्व भी इसी तरह किया गया।

हमसे सुखी और ताकतवर वे लोग हैं जिन्होंने समाज को बड़ा सपना दिखाकर शक्ति इकट्ठा करने का महारत हासिल कर लिया है। बस एक ही बात कहना है कि सत्ता प्राप्ति करो, सारी समस्याओं का निवारण तुरंत हो जाएगा। सत्ता वह चाभी है जिससे सारे बंद ताले खुल जाते हैं। यह सच है कि राजनैतिक सत्ता की ताकत सबसे बड़ी होती है। दलितों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों को यहीं से अधिकार एवं सम्मान मिलते हैं। परिस्थितियां बदली हैं और अब कुछ बंद ताले संसद से खुलते हैं तो कुछ उच्च न्यायपालिका से। मीडिया एवं उद्योग जगत भी कुछ बंद तालों को खुलवाने में सक्षम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे दो जजों ने चंद मिनटों में फैसले दे दिए कि जो दो वर्ष से ज्यादा की सजा प्राप्त कर चुका हो, उसकी संसदीय व विधायिका की सदस्यता खत्म कर दी जाए। हो सकता है कि संसद को ऐसा कानून बनाने में सालों लग जाते हैं क्योंकि वहां की प्रक्रिया जटिल है और विपक्ष भी बैठा हुआ है। आज से कुछ साल पहले क्या सोचा गया था कि क्या न्यायपालिका कानून बनाने का काम करने लगेगी, जो केवल जनप्रतिनिधियों का अधिकार है? यह सरेआम असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक कार्य उच्च न्यायपालिका कर रही है। संसद में जिन्हें यह बोलना चाहिए था वह भ्रष्टाचार के मामले में गले तक फंसे हुए हैं तो इसे कौन उठाए?

इस देश की चुनावी राजनीति बिना काले धन के असंभव हो गई है अतः पूंजीपतियों का नियंत्रण सत्ता पर अच्छा–खासा हो गया है। एक बार जिसके विरूद्ध में खड़े हो जाएं, मजाल है कि सरकार कुछ कर सके उदाहरण के रूप में निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए सरकार ने विभिन्न समितियां बनाकर के कवायद शुरू की तो उद्योग जगत अड़ गया और अभी तक कोई प्रगति नहीं हो सकी और जब तक बड़ा आंदोलन नहीं होगा तो संसद से कानून बनवाना असंभव है। बड़े आंदोलन की तैयारी में सदा अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ प्रयासरत् रहता है। मीडिया भी जिस काम को कराने व न कराने की ठान ले तो राजनैतिक सत्ता को कई बार कदम पीछे खींचना पड़ता है।

जब तक सत्ता न मिले चाहे जितने जुल्म हों, आरक्षण समाप्त हो जाए, कर्मचारियों–अधिकारियों की नाना प्रकार की प्रताड़ना, खाली पदों के ऊपर भर्ती न होना, भूमिहीनों को भूमि न देना, न्यूनतम मजदूरी से वंचित करना, सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा, बलात्कार व हत्या, नए नौकरियों का सृजन न होना आदि बुनियादी समस्याओं पर न कुछ बोलना, न संघर्ष करना, संसद व विधानसभाओं में भी पूरे मन से सवाल न उठाना, धरना–प्रदर्शन आदि सब बंद। गत् दो–तीन दशक से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सत्ता प्राप्ति के नशे में निकम्मा बनकर के बैठा है और परिणाम यह हुआ कि चारो तरफ अत्याचार बढ़े हैं, अधिकारों में कटौती हुई है और नए अधिकारों की मांग आदि के प्रति संवेदनहीनता। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने यह तो नहीं कहा कि जब सत्ता मिलेगी तभी वे मान–सम्मान व अधिकार दिला सकेंगे। समयातंराल और परिस्थितिजन्य दिन प्रति दिन के आधार पर उन्होंने संघर्ष किया चाहे वह मंदिर प्रवेश की बात थी या तालाब के पानी का इस्तेमाल, आरक्षण, बौद्ध धर्म की दीक्षा, मजदूरों को संगठित करना एवं सामाजिक कुरीतियों को मिटाना। सत्ता भी प्राप्त हो जाए तो जादू नहीं हो जाएगा कि रातोंरात उत्थान हो जाए। परिसंघ पूरी तरह से सत्ता प्राप्ति करने में यकीन करते हुए दिन प्रति दिन के आधार पर संघर्ष करना और जागृति पैदा करना में यकीन करता है। अतः पूर्ण जिम्मेदारी भरा कार्य न कि बिना कुछ किए सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य को दिखाकर समाज का साधन, समय, संसाधन का इस्तेमाल करते जाना। सत्ता में आने पर भी तुगलकी फरमान न कोई मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री जारी कर सकता है कि जो वह चाहे कानून बना दे। पक्ष और विपक्ष भी है और कानून और अधिकार देने की एक प्रक्रिया होती है। सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास हमेशा के लिए नहीं आती बल्कि उसका स्थानांतरण होता रहता है। अतः जो लोग सत्ता प्राप्ति के नशे में आंदोलन का राह छोड़ चुके हैं वह समाज को दे नहीं रहे हैं बल्कि मूर्ख जरूर बना रहे हैं।

परिसंघ न केवल इस तरीके का खंडन करता है बल्कि अनवरत् संघर्ष के साथ सत्ता की प्राप्ति में यकीन। कुछ दलित कर्मचारी–अधिकारी और बुद्धिजीवी केवल समाज को जगाने के नाम पर साधन, समय एवं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह एक कथावाचक की भूमिका निभा रहे हैं। दुश्मन की आलोचना करने में अच्छा तो लगता ही है। इसलिए जब ये लोग ब्राह्मणवाद पर हमला करते हैं तो हमारे लोगों को अच्छा लगता है। इससे मानसिक तुष्टि मिलती है। ब्राह्मणवाद के द्वारा बिछाए गए परंपराएं, कुरीतियां, अंधविश्वास एवं भाग्यवाद आदि पर हमला इस तरह बोलते हैं कि मानों भाषण और शब्दों से यह खत्म हो जाएगा जबकि विकल्प का सुझाव नहीं देते ओर न व्यवहारिक कार्यक्रम का। ब्राह्मणवाद का विकल्प बौद्ध धर्म या नास्तिकता हो सकता है तो क्या ये लगभग 30 साल में ये कर सके? सरकारी नौकरियों में आरक्षण जरूरी इसलिए ही नहीं है कि जो लोग विभिन्न पदों पर आसीन हैं उन्होंने अपनी जिंदगी बेहतर कर ली है बल्कि वह समाज की सोच है। जिस समाज की सोच खत्म हो जाती है वह प्रतिष्ठा, भागीदारी एवं अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकती। कालिदास की कहावत चरितार्थ है कि जिस डाल पर बैठा उसी को काट्ना और यह यहां सटीक बैठती है और यही कर्मचारी–अधिकारी स्वयं आरक्षण का लाभ लेकर इस स्थिति में पहुंचे हैं वे ही आरक्षण की लड़ाई तो लड़ना दूर, यह कहते दिखते हैं कि हम देनेवाले बनेंगे। देनेवाले हम हों इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती लेकिन क्या तब तक जो भागीदारी व अधिकार हमारें हैं उसे छीनने दें, सुरक्षित करने के लिए संघर्ष न करें। उदारीकरण ने हमारी भागीदारी कम ही किया है और आनेवाले दिनों में आसार अच्छे नहीं हैं तो उस परिस्थिति में क्या हम कभी देनेवाले हो सकेंगे? देनेवाले हम तभी हो सकते हैं जब दिन प्रति दिन के आधार पर आवाज उठाएं, संघर्ष करें और जहां भी संभव है अधिकार को जीतें। वैकल्पिक संस्कृति एवं धर्म की स्थापना करने के लिए व्यवहार में उतरें।

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने कोई बड़ा सपना नहीं दिखाया और न ही शक्ति को सिद्धांत तक ही सीमित रखा। सिद्धांत एवं व्यवहार को सामंजस्य बनाया और यही कारण है कि उसके संघर्ष की वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ और आरक्षण बचा। 4 नवंबर 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर के वैकल्पिक सांस्कृतिक लड़ाई लड़ा। पिछड़ों को जब उच्च शिक्षण संस्थान

शेष पृष्ठ 3 पर ...

परिसंघ की रैली की तिथि एवं स्थान में बदलाव

आगामी शीतकालीन संसद सत्र की तिथि में बदलाव के कारण परिसंघ की रैली जो 25 नवंबर को होनी थी वह अब 16 दिसंबर, 2013 को होगी। साथ ही रामलीला मैदान के स्थान पर रैली अब दिल्ली के जंतर-मंतर पर होगी।

-डॉ. उदित राज
(राष्ट्रीय अध्यक्ष)

विश्व के सभी धर्मों पर बौद्ध धम्म की प्रमाणिकता श्रेष्ठ

बौद्ध धर्म की लोकप्रियता आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। ऐसा अकारण नहीं हुआ है। इस गहन चर्चा के कारण अति उत्साहजनक दो समाचार हैं : पहला समाचार, बौद्ध साधना पद्धति के उत्साहपूर्वक परिणामों को साबित करते हुए दिनांक 2 नवंबर 2012 के दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र (नई दिल्ली) में प्रकाशित हुआ था, जो इस प्रकार है :

''वैज्ञानिकों ने तलाशा दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान'' लंदन, एजेंसियां : हर इंसान चाहता है कि वह खुश रहे। उसे किसी बात की फिक्र न सताए, कोई गम न हो। मगर चाहकर भी ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन एक बौद्ध भिक्खु ऐसा है जिसे सचमुच कोई गम नहीं है और वह दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान है। वैज्ञानिकों ने 66 वर्षीय मैथ्यू रिकर्ड को दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति बताया है। रिकर्ड के मस्तिष्क की स्कैनिंग का अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह दावा किया। करीब 40 साल पहले रिकर्ड ने भौतिकवादी दुनिया से मुंह मोड़ लिया था और बोधि की प्राप्ति के लिए भारत आ गए थे। तब से उनका अधिकांश समय ध्यान (मेडिटेशन) में गुजरता है। रिकर्ड इसे ही अपनी खुशी और संतुष्ट जीवन का रहस्य बताते हैं। वह तिब्बत के अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा के भी बेहद करीबी हैं। पूर्व में हुए अध्ययन में ध्यान के कई फायदे सामने आ चुके हैं, लेकिन इस अध्ययन से पता चला है कि यह इंसान के खुश रहने की क्षमता को बढ़ा देता है।

विस्कांसिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में सैकड़ों लोगों को शामिल किया था जो नियमित ध्यान करते थे। प्रमुख शोधकर्ता व न्यूरोसांइटिस्ट, रिचर्ड डेविडसन ने मैथ्यू के मस्तिष्क की स्कैनिंग करने के लिए उनके सिर पर कई तार लगाए, जिनसे 256 सेंसर जुड़े थे। उन्होंने पाया कि मैथ्यू जब बहुत गहराई में जाकर ध्यान करते हैं तो उनके मस्तिष्क से गामा तरंग उठती है। ये तरंगे चेतना, सावधानी और याददाश्त से जुड़ी होती है और रिकर्ड को खुश होने का अनुभव देती है। डेविडसन ने बताया कि इससे पहले किसी भी स्कैनिंग में इस तरह के परिणाम मिले थे। वैज्ञानिकों ने रिकर्ड के मस्तिष्क के बाएं हिस्से में स्थित प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स में भी बहुत सक्रियता पायी, इस कारण भी उन्हें बहुत ऊंचे स्तर पर खुश रहने की अनुभूति होती है, साथ ही नकारात्मकता का स्तर घटता चला जाता है।

शोधकर्ताओं ने इस अवस्था को 'न्यूरोप्लास्टिसिटी' नाम दिया है। उनका कहना है कि यह अध्ययन इस बात को समझने में एक नई दिशा होगी कि क्यों कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाते।''

अभी कुछ ही दिन बीते थे, तुरंत ही दूसरा समाचार भी बौद्ध साधना पद्धति के महत्व को जताने वाला प्रकट हो गया। यह समाचार दिनांक 12 दिसंबर 2012 के 'राष्ट्रीय सहारा' नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। समाचार इस प्रकार था :

''ब्रिटेन के 4000 सैनिक बोधगया आएंगे'' : ब्रिटेन के सैनिक अफगान व इराक युद्ध में लड़ने के कारण मनोवैज्ञानिक बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। मनोवैज्ञानिक बीमारी ''पोस्ट ट्रामैटिक स्ट्रेस डिस्आर्डर (पीटीएसडी)'' से पीड़ित ऐसे 4000 सैनिकों को तनाव व मानसिक दबावों से उबरने के लिए बिहार स्थित बोधगया भेजा जाएगा। ब्रिटेन के सैनिकों के दल जनवरी के पहले सप्ताह से बोधगया आना शुरू करेंगे और महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाएंगे।

ब्रिटेन ने जनवरी के पहले सप्ताह से 100-150 सैनिकों के दल को बोधगया भेजने की योजना बनाई है। ब्रिटेन के सैनिक बोधगया आकर ध्यान आदि लगाना सीखकर युद्ध की विभीषिका से उबरने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के सैनिक बोधगया के पवित्र वृक्ष ''महाबोधि'' के नीचे ध्यान लगाएंगे। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सैनिक छः दिन बोधगया में बिताएंगे और एक दिन उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ में व्यतीत करेंगे।

बिहार के पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि ब्रिटेन क सैनिकों के अलग-अलग दल लगभग पूरे साल बिहार आएंगे। लंदन में 5 से 8 नवंबर के दौरान आयोजित वर्ल्ड टूरिज्म मार्ट में ब्रिटेन और बिहार के बीच समझौता हुआ था।''

एक समय ऐसा था, जब इस देश के चप्पे-चप्पे पर बौद्ध धम्म एवं संस्कृति का प्रभाव व्याप्त था घर-घर में शील-सदाचार के पालन के साथ ही बौद्ध साधना का अभ्यास किया जाता था। यह वही युग था जब इस देश में लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। यही कारण है कि प्राचीन पाली साहित्य में 'ताला (Lock)' शब्द ढूंढने पर भी नहीं मिलता। जब तक इस देश में बौद्ध धर्म का साम्राज्य रहा इस देश पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित सत्य है कि ज्यों ही इस देश से बौद्ध धम्म को बलपूर्वक खदेड़ा गया, त्यों ही यह भारत देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता गया। विदेशियों के षड्यंत्र भी सफल होने लगे और आक्रमण भी। सदियों तक हमारा देश गुलाम रहा।

यहां मुझे भूतपूर्व गृहमंत्री भारत सरकार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल (तत्कालीन) पंडित कैलाश नाथ काटजू जी के प्रेरणादायी शब्द याद आ रहे हैं, जो उन्होंने सारनाथ स्थित मूलगंधकुटी विहार, सारनाथ के उद्घाटन के अवसर पर कह रहे थे :

''जब बौद्ध धर्म का इस देश से लोप हुआ, उसी दिन से यह महान देश, विदेशियों के शोषण

और गुलामी का शिकार बना। 900 वर्षो तक यह देश गुलाम रहा, जिसमें 700 वर्ष मुगलों की गुलामी और 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी रही। जिस दिन से बौद्ध धम्म के पुनरोद्धार की बात आरंभ हुई उसी दिन से भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन आरंभ हुआ। इसका यही अर्थ है कि बौद्ध धर्म मंगलकारी और कल्याणकारी सधर्म है। इसका ध्येय स्वराज्य स्थापित करना था। इसके अतिरिक्त जिस दिन बौद्ध धर्म को इस देश से खदेड़ा गया उसी दिन से भारत की जनता विदेशी आक्रमणों का शिकार हो गई। इन 900 वर्षो का इतिहास मुगलों और अंग्रेजी शासकों का इतिहास है। इन दोनों नस्लों के शासनकाल में मंगलकारी धर्म-बौद्ध धम्म के स्थान पर शनैः-शनैः अत्याचारी धर्म (मनुवाद/सनातन धर्म/ब्राह्मणवाद) ने स्थान लिया। यही 'ब्राह्मणवाद' की इस देश को महान देन है।

इस सत्याधारित ऐतिहासिक कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'बौद्ध धर्म और स्वतंत्रता (Liberty)' का चोली दामन का साथ है। बौद्ध धम्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बाद भी अब वह दमदार तरीके से लौट रहा है। निःसंदेह बौद्ध धर्म की यह सुखद आहट हमें बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर जी के कुशल प्रयासों के परिणामस्वरूप ही सुनाई देने लगी है।

लगे हाथों हम यह भी बताते चलें कि स्वीट्जरलैंड से प्रकाशित, 15 जुलाई 2009 को 'ट्रिब्यून डि सिल्वा' नामक समाचारपत्र के अंक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संसार के सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला गया कि बौद्ध धर्म ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अपने सुधी पाठकों के लिए उक्त समाचार को यहां पर यूं का यूं ही प्रस्तुत किया जा रहा है :

''सर्वश्रेष्ठ धर्म पुरस्कार बौद्ध धम्म को''

जेनेवा स्थित कोलिशन फॉर दि एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन्स एंड स्प्रिचुअलिटी' (आईसीएआयूएस) ने 'विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म' का पुरस्कार इस वर्ष बौद्ध समुदाय को दिया है।

इस पुरस्कार का निर्णय आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रत्येक हिस्से के 200 से भी अधिक धर्म गुरूओं के एक अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन ने किया। यह देखना अपने आप में मन मोहित कर देने वाला था कि अनेक धर्मगुरूओं ने अपने धर्म को नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को ही मत दिया। हालांकि आईसीएआरयूएस की सदस्यता के मामले में बौद्धों की संख्या बहुत ही कम है। यहां चार मतदाता सदस्यों की टिप्पणियां दी जा रही है :

आईसीएआरयूएस के शोध निदेशक जोना हलट महोदय के अनुसार, ''मेरे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बौद्ध धर्म को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म का पुरस्कार मिला, क्योंकि शब्दतः हमें बौद्ध धर्म के नाम पर लड़े जाने वाले युद्ध का एक भी उदाहरण नहीं मिला, जबकि अन्य सभी धर्म बगल में बंदूक रखे दिखाई देते हैं कि कहीं कोई ईश्वर (की शान में) गलती करें तो (उसे तुरंत गोली मार देंगे)। हमें बहुत कोशिश करने पर भी ऐसा एक भी बौद्ध नहीं मिला जो कभी किसी (आतंकी) सेना में रहा हो। ये लोग (बौद्ध धम्म आवलंबी) जो उपदेश देते हैं और उनका जिस सीमा तक पालन करते हैं ऐसे उपदेश और उनका पालन करने की यह सीमा, किसी अन्य आध्यात्मिक परम्परा में विद्यमान है; ऐसा हम किसी अन्य आध्यात्मिक परंपरा में दर्ज (Record) नहीं कर सके।''

एक कैथोलिक पादरी फादर टेड ओ शॉनेसी ने बेलफासट में कहा : ''जितना मैं कैथोलिक चर्च से प्रेम करता हूं, मैं इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहा हूं कि हम अपने धर्मशास्त्र में प्रेम का उपदेश देते हैं और फिर भी जब बात अन्य इंसानों की हत्या करने की आती है तो हम परमेश्वर की इच्छा ज्ञात होने का दावा करते हैं (कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी)। इस कारण, मुझे अपना मत (वोट) बौद्धों के पक्ष में ही डालना पड़ा।''

पाकिस्तान के एक मुस्लिम मौलाना ताल बिन वसाद ने अपने अनुवादक से इस बात पर सहमति जताई : ''वैसे तो मैं एक कट्टर धार्मिक मुसलमान हूं, फिर भी मैं देख सकता हूं कि कितना गुस्सा और खून-खराबा एक समस्या को निजी स्तर पर सुलझाने के बजाय धार्मिक अभिव्यक्ति में झोंका जाता है। बौद्धों ने इसका हिसाब कर रखा है।'' पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय की ओर से आईसीएआरयूएस के मतदाता सदस्य बिन बसाद ने आगे कहा : ''दरअसल, मेरे कुछ सबसे अच्छे दोस्त बौद्ध है।''

और येरुशलम के रब्बी शमुएल बासरस्ताइन ने कहा : ''बेशक मैं यहूदी धर्म से प्रेम करता हूं और सोचता हूं कि यह दुनिया का महानतम धर्म है। लेकिन ईमान से कहूं, तो मैं 1933 से ही हर दिन मिनयान (दैनिक यहूदी प्रार्थना) से पहले विपस्सना (बौद्ध साधना का एक प्रकार) करता आ रहा हूं। इसलिए मैं इसे समझता हूं।''

बहरहाल, इसमें एक बाधा थी आईसीएआरयूएस को ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे यह पुरस्कार (सम्मान) दिया जाता। उन्होंने जिस भी बौद्ध से संपर्क किया उसने यही कहा कि हमें इस (अवार्ड) की जरूरत नहीं है।

जब पूछा गया कि बर्मी बौद्ध समुदाय ने पुरस्कार लेने से मना क्यों किया, तो बर्मी के भंते गुराटा हंटा ने कहा : ''हम इस सम्मान को समस्त मानवता को समर्पित करते हैं, क्योंकि बुद्ध स्वभाव हम सब में है।'' ग्रोहलिचेन ने आगे कहा : ''हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हमें ऐसा बौद्ध नहीं मिल जाता जो इसे स्वीकार कर लेगा। जब ऐसा होगा तो हम आपको सूचित भी कर देंगे।''

उक्त सभी समाचार भारत की सीमा के बाहर से आए हैं। गलती से भी हमें इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए कि बौद्ध धम्म के श्रेष्ठत्व को सिद्ध करने वाली घटनाएं भारत में घटती ही नहीं है। केवल अंतर इतना है कि हमारे देश का प्रबल मीडिया और दबंग शासक वर्ग ने अपनी सारी योग्यता एवं क्षमता एक 'धर्म विशेष' को महिमा मंडित करने के लिए ही झोंक रखी है। इंग्लैंड के हजारों सैनिकों में व्याप्त मानसिक विकृतियां उन बाबाओं और धर्म गुरूओं को झकझोरने के लिए काफी हैं जो साधना और योग के नाम पर पेट पूजा और अंधविश्वास के विषवृक्ष रोपने में लगे हुए हैं। इससे अधिक मैं और क्या कहूं-हमारे पाठक बहुत ही बुद्धिमान हैं, जो मैं नहीं कह पा रहा हूं, उसे वे बखूबी समझ रहे हैं।

भवतु सब्बमंगलं

(साभार : शिल्पकार टाइम्स)

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि अपनी ओर से भी छपवाकर वितरित करें व तैयारी अभी से शुरू कर दें

परिसंघ के आह्वान पर निजी क्षेत्र में आरक्षण एवं आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए रैली

16 दिसंबर, 2013 (सोमवार) को प्रातः 11 बजे लाखों की संख्या में जंतर-मंतर, नई दिल्ली में एकत्र होकर संसद का घेराव करें

साथियों,

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 1997 में हुई। यह तब हुई थी जब पांच आरक्षण विरोधी आदेश भारत सरकार ने जारी किए। इसके महान संघर्ष की वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुए तभी जाकर के आरक्षण बचा। इस संघर्ष की 11 दिसंबर 2000 की रैली इतनी बड़ी थी कि आजाद भारत के 10 बड़ी रैलियों में से एक मानी गई थी जिसके प्रभाव से आरक्षण बचा (हिंदुस्तान समाचार की रिपोर्ट)। 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बनें। निजी क्षेत्र में आरक्षण के महत्व को जब तक लोग समझ नहीं पाए थे तब से परिसंघ ने उठाया और अब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। 2006 में जब पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला तो परिसंघ ही संघर्ष करके विरोध को दबाया और आरक्षण लागू कराया। अन्ना हजारे ने जब हठ किया कि लोकपाल बने और वह संविधान से भी ऊपर हो तो हमीं ने उसका जवाब दिया। बहुजन लोकपाल बिल पेश किया और इसी से संसद में जब लोकपाल पर बहस हुई तो आरक्षण का प्रावधान रखा। कुल मिलाकर 1997 से लेकर अब तक परिसंघ ही एकमात्र संगठन रहा जिसने नतीजा देने वाली लड़ाई लड़ी। शेष अधिकतर संगठन चंदाखोरी, सभा–सम्मेलन और कैडर करने में ही लगे रहे।

निजी क्षेत्र में आरक्षण जिंदगी और मौत का प्रश्न बन गया है। यूपीए प्रथम के समय में सरकार कुछ गंभीर थी लेकिन जब हम थोड़ा अपने ही लोगों के द्वारा टांग खिंचाई से कमजोर हुए तो सरकार के ऊपर दबाव कम हुआ और अभी तक निजी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए कानून नहीं बना। हमारे कमजोर होने से पदोन्नति में आरक्षण उत्तर प्रदेश में छीना क्यूंकि वहां के कर्मचारियों ने 4 जनवरी 2011 के बाद से भी हमारा साथ नहीं दिया। इसी दिन लखनऊ हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का फैसला लिया था। फैसले के अंतिम पैराग्राफ में उल्लेख भी था कि राज्य सरकार चाहे तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एम. नागराज के फैसले में शर्तों को पूरा करते हुए आगे इस अधिकार को यथास्थिति रख सकती है। उसने ऐसा ना करके सुप्रीम कोर्ट में चली गई और 27 अप्रैल 2012 को फिर से उल्टा आ गया। नागराज की तीन शर्तें– पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व और दक्षता गलत हैं क्यूंकि 77वां, 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधनों में ऐसा नहीं है। आरक्षण कानून बनाने के लिए 2004 से बिल लंबित है और अभी तक यह संसद से पास नहीं हो सका है।

निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की वजह से जिसके पास धन है उसी की मीडिया, सत्ता और तमाम ताकतें है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई है। ऐसे में यदि दलित आदिवासी को आर्थिक सत्ता में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण, कैडरकैम्प, तकनीकी सहायता, कर्ज, बाजार, नेटवर्क, मांग एवं पूर्ति आदि के लिए इन्हें तैयार नहीं किया गया तो ये गुलाम ही रह जाएंगे।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त सफाई कर्मियों का बेतहाशा शोषण और इस कार्य में ठेकेदारी प्रथा है। उच्च न्यायपालिका एवं सेना में आरक्षण आदि बड़ी समस्याएं हैं। जाति–प्रमाणपत्र जारी होने में परेशानी और एक राज्य का दूसरे राज्य में ना मान्य होना, नौकरी में भारी नुकसान है। हमारे सामने दलित एकता की बड़ी चुनौती है। जब तक हम बाबा साहेब एवं अपने पूर्वजों के विचारधारा को दलित समाज के समस्त जातियों में जो कम अंबेडकरवादी हैं जैसे बाल्मिकी, खटिक, मादिगा, पासी, धानुक, धोबी, कोली आदि में नहीं फैलाते हैं, तब तक हमारी संख्या और एकता कम रहेगी और उपरोक्त अधिकारों को हासिल करना मुश्किल होगा। परिसंघ आह्वान करता है कि अब आप गैर–अंबेडकरवादियों के बीच जाकर अपने ताकत को बढ़ाएं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है और प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी चाहते हैं।

उपरोक्त मांगों को लेकर के 16 दिसंबर 2013 को प्रातः 11 बजे नई दिल्ली स्थित जंतर–मंतर पर लाखों की रैली के उपरांत प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

निवेदक : इंदिरा आठवले, प्रधान महासचिव

भवनाथ पासवान, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह (उ0प्र0), एस.यू. गडपायले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), महासिंह भूरानिया, एस. पी. जरावता, फूल सिंह गौतम, दीपक पायलट (हरियाणा), जसबीर सिंह पाल, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो.– 9871237186), डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, ललित कुमार, आर. सी. मथुरिया, ब्रह्म प्रकाश, ए. आर. कोली (दिल्ली), इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), आर.वी. सिंह, हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), डी.के. बेहरा, डॉ. के. सी. मल्लिक, शंखानंद, नारायन चरन दास (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, आर.बी. सिंह (म.प्र.), आर. एस. मौर्या, दीपक पटेल (गुजरात), जी. रंगनाथन, बी. सगादेवन, एम. पी. कुमार (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, प्रेम कुमार, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, तारापद बिश्वास, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विनय मुंडू (झारखण्ड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरुषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
पत्राचार : टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–1, फोन : 23354841–42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

शेष पृष्ठ 1 का ...

हमारा जुर्म

में आरक्षण मिला तो उसके लिए संघर्ष किया। निजी क्षेत्र में आरक्षण का सतत् प्रयास चल रहा है। आगामी 16 दिसंबर को निजी क्षेत्र व पदोन्नति में आरक्षण, सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा का खात्मा, शिक्षा में निजीकरण पर रोक आदि मुद्दों को लेकर विशाल रैली जंतर–मंतर, दिल्ली में की जा रही है। लोकपाल जब भी बनेगा दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलकर के रहेगा और यह परिसंघ के संघर्ष से ही संभव हुआ। दिन प्रति दिन के आधार पर लाखों कर्मचारियों–अधिकारियों और पीड़ितों के मामलों को पत्राचार, ज्ञापन एवं संघर्ष के द्वारा उठाते ही रहते हैं। इस मार्ग से होते हुए सत्ता की प्राप्ति होनी चाहिए। विकल्प दिए बगैर समाज को जगाने के नाम पर ब्राह्मणवाद के आलोचना से परिवर्तन संभव नहीं है। हमारा जुर्म यही है कि हम जिम्मेदार हैं और समाज का एक–एक कतरा का सहयोग सही इस्तेमाल करते रहे हैं लेकिन जो सहयोग हमें मिलना चाहिए था नहीं मिला। देखना है इस बात का कि कितना असर पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इस विचार को जन–जन तक पहुंचाया जाए और फिर भी संदेह हो तो हम आगे स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं।

जो निजी क्षेत्र में आरक्षण का वायदा न करे, उसका चुनाव में बहिष्कार

नेशनल एससी/एसटी/ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फेडरेशन (नसोसवायएफ) का निर्माण इसलिए हुआ कि राष्ट्र स्तर पर इस प्रकार का एक भी संगठन नहीं है। कांग्रेस का संगठन एनएसयूआई, बीजेपी का एबीवीपी, सीपीएम का एसएफआई और इस तरह से और पार्टियों के संगठन है लेकिन एससी/एसटी/ओबीसी का एक भी नहीं। बिना किसी पार्टी या बड़े सामाजिक संगठन के संरक्षण के विद्यार्थियों एवं नौजवानों का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर चल नहीं सकता और जो स्थानीय स्तर पर हैं तो उनका उत्थान और पतन होता रहेगा। प्रथम बार अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज के संरक्षण में इसकी स्थापना हुई है। परिसंघ की शाखाएं पूरे देश में है और इसका प्रबुद्ध नेतृत्व नसोसवायएफ को हर स्तर पर सहयोग देगा। परिसंघ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का देश का एक बड़ा संगठन है। आरक्षण बचाने की लड़ाई इसी के नेतृत्व में लड़ी गयी और लगातार संघर्ष जारी रहता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर जब कांग्रेस और भाजपा आदि की विचारधारा हमारे छात्रों को दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से वे सही चेतना से वंचित होते हैं। ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षा खत्म होने के बाद वैचारिक रूप से समाज उत्थान करने में वे सक्षम होंगे? हमारी शिक्षा रोजगार लेने के लिए दी जाती है न कि नयी सोच पैदा करने के लिए। बहुतायत को पता ही नहीं है कि जाति व्यवस्था का आर्विभाव कब हुआ, इसके क्या घातक परिणाम हैं और इससे निजात पाने के लिए विकल्प क्या है? ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र क्या है? किस तरह से बहुजनों को हजारों जातियों में बांटकर राज करो की नीति अपनायी। जिन महापुरुषों जैसे ज्योतिबा फूले, शाहूजी महाराज, भगवान गौतम बुद्ध, कबीर दास, डॉ. अंबेडकर ने संघर्ष किया और दर्शन दिया, उसके बारे में कॉलेज और विश्वविद्यालयों के समय में जानकारी मिल ही नहीं पाती। इस समय यदि सही विचार दे दिए जाएं तो देश में समतामूलक समाज स्थापित हो सकता है।

वर्तमान में मिजोरम, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। किसी पार्टी के घोषणा-पत्र में एससी/एसटी/ओबीसी के छात्रों एवं नौजवानों को रोजगार, महंगाई को देखते हुए छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी एवं छात्रावास आदि सुविधा की बात शामिल नहीं है। सरकारी नौकरियों के घटने के साथ ही इन वर्गों में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है। जाति व्यवस्था की वजह से बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को रोजगार निजी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ने से आसानी से मिलता जा रहा है लेकिन हम कहां जाएं? जिस रफ्तार से उदारीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां घट रही हैं तो वह दिन दूर नहीं जब शत्-प्रतिशत एससी/एसटी/ओबीसी के छात्र व नौजवान अच्छी से अच्छी शिक्षा धारण करके बेरोजगार रह जाएंगे। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं तो समझो कि पढ़ाई-लिखाई का कोई मतलब नहीं रह गया। मां-बाप मेहनत और मजदूरी करके भले ही कोचिंग भी करवाएं तो भी कितने को सफलता मिलेंगी?चुनाव के समय ही अपने हक को सही ढंग से मांगा जा सकता है। हम छात्र व नौजवान सभी पार्टियों के सामने वार्तालाप, धरना-प्रदर्शन आदि करके इस मांग को रखें, जो हमारी बात मानें उसको समर्थन दें नहीं तो बहिष्कार। यदि कोई पार्टी बात नहीं मानती है तो हम सबका बहिष्कार करके एक क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण करेंगे।

न धन में, न धरती में, न उद्योग में, न मंदिर में, न शिक्षण संस्थानों में, न मीडिया में हमारी भागीदारी है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग भी पूरे हक की नहीं है। वास्तव में इन क्षेत्रों में भागीदारी की मांग करना चाहिए। क्या हमारी छोटी सी भी मांग देश में नहीं मानी जा सकती है? देश के जो बड़े उद्योगपति हैं यदि वे सोचते हैं कि हजारों-लाखों करोड़ का कारोबार उनका निजी है तो यह गलत है। हम बहुजन कच्चे वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण करते हैं। इनके उद्योगों में काम करते हैं और उसी से सवर्ण मुनाफा कमाते हैं। सरकार जनता की है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी जनता की है। यदि पुलिस की सुरक्षा न दी जाए तो क्या निजी कंपनियां व कारोबार अस्तित्व में रह सकते हैं? बिजली, सड़क, कानून-व्यवस्था आदि जनता की चुनी हुई सरकार की होती है। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं या दी जा रही सेवाएं यदि बहुजन समाज उपभोग न करें तो क्या उनकी खपत हो सकती है और मुनाफा कमा सकते हैं? हम कौन सी बड़ी मांग कर रहे हैं। यदि मांग है तो केवल रोजगार पाने की न कि हिस्सेदारी की जबकि होना चाहिए। अनुसूचति जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ कई वर्षों से निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है लेकिन अभी तक संसद में कोटा देने के लिए कानून नहीं बनाया। आगामी 16 दिसंबर को दिल्ली में इन मांगों को लेकर विशाल रैली होगी जिसमें भारी संख्या में शामिल होना है। ज्ञात रहे कि यूपीए प्रथम के समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह मांग शामिल थी। यदि हमारा नेतृत्व कमजोर, भ्रष्ट और बिकाऊ न होता तो यह अधिकर हमें मिल गया होता। इन्हीं के कारण हमें भी आवश्यक सहयोग समाज से नहीं मिल पाता वरना हमारे प्रभाव से ही ये मामले हल हो गए होते। छात्रों व नौजवानों से आह्वान है कि वे सड़कों पर उतरे, संघर्ष करें, सहयोग दें, जेल भरें वरना शिक्षित होकर के भी बेरोजगार रहना पड़ेगा।

-डी. हर्षवर्धन

पिछले अंक का शेष...

उत्तराखंड : मनुष्य निर्मित विनाश

रमणिका गुप्ता

दूसरा मुद्दा है अनुशासन का। देवघर में शिव के दर्शन करने हों, तो पंडित को पैसा दे दीजिए, बस दस हजार की भीड़ कतार में बाहर लगी होने के बावजूद आप दर्शन कर लेंगे। फिर अनुशासन भी क्या दरकार? क्यों कोई कतार में लगे?

तीसरा मुद्दा है अंधविश्वास/आस्था है, विश्वास है तो सोचने की क्या दरकार? बस विश्वास करो। जो धर्मग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उसे मानो। बस कर्म करो, फल की इच्छा न करो। यानी मेहनत करो उसके एवज में मजदूरी भी न मांगो। मरने के बाद स्वर्ग में फल मिल ही जाएगा या अगले जन्म में किसी बड़े घर में पैदा हो जाएगा, तो पौ बारह हो ही जाएगी। इस जन्म में दुःख है तो क्या हुआ, अगला जन्म तो ठीक होगा ना! यह स्वर्ग या अगला जन्म किसने देखा है, जिसके भरोसे जनता को पुरुषार्थहीन बना दिया जाता है?

रह गई सरकार द्वारा व्यवस्था की बात। आपात स्थिति में राहत की व्यवस्था जरूर पहले सोचकर रखनी चाहिए लेकिन यह समय राजनीति की नहीं है। आपातकालीन व्यवस्था क्या हो सकती थी, सिवाय इसके कि इनका सूचना तंत्र ठीक रहता तो विनाश का कुछ आभास पहले मिल जाता या राहत की सामग्री तैयार रहती तो समय पर दी जा सकती थी। लोग भूख से तो नहीं मरते या घटनास्थलों से ढ़ो कर लाने में देरी के कारण तो मारे नहीं जाते। लेकिन हम भी तो कम दोषी नहीं है। हमारे लोग भी तो जब तक पानी सर तक न पहुंच जाए-घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। बिहार में आई 1975 की बाढ़ का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं।

उत्तराखंड की सड़कें टूट गयी हैं। अब सड़क कोई ऐसा उपस्कर तो नहीं कि बनाकर स्टोर में रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत बिछा दी जाए कि लोग उस पर चलकर आ जाएं। हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज उपलब्ध करा दिए हैं और सेना लोगों को ला भी रही है। रही बात सरकार, प्रशासन, अफसर, पुलिस व अधिकारियों की निष्ठा से काम करने की। इस पर सवाल जरूर उठ सकते हैं। योजनाओं को समय पर पूरा न करने पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है। आपातकाल की तैयारी पर कोताही बरतने का आरोप भी अपनी जगह सही हो सकता है। लेकिन आरोप लगाने से पहले एक किस्सा सुनें। मिर्ची से भूत भगाया जाता है लेकिन जब मिर्ची में ही भूत घुस जाए, तो कैसे भागेगा भूत? भूत ही मिर्च का आदी जो जाए, तो क्या हश्र होगा आप समझ सकते हैं? यहां तो मिर्च में ही भूत घुस गया है। पूरा का पूरा 'आवा' ही ऊत गया है। सारा प्रशासन आज नहीं, पहले से ही भ्रष्ट है। फिर उत्तराखंड की दुर्घटना से प्रशासन का रवैया एकाएक कैसे बदल जाएगा? जिन्हें हर आपातकाल पैसा बनाने का जरिया नजर आता हो। उनसे यह उम्मीद की जा सकती है? ये नौकरशाही भी जनता के बीच से ही आती है। उसकी मानसिकता बदलने के लिए व्यवस्था बदलनी होगी और व्यवस्था बदलने के लिए सरकार की नहीं, जनता की दरकार होती है। जनता का हथियार होता है क्रांति। क्या हम क्रांति के लिए तैयार हैं? शायद नहीं। हम तो बहुत धैर्यवान लोग हैं। भगवान का नाम लेकर किसी की इज्जत लूट लेते हैं या अपनी बहू-बेटी की इज्जत गंवाने को तैयार रहते हैं। भगवान का नाम लेकर किसी की हत्या तक कर देते हैं। इंसान की मार भी सह लेते हैं और प्रकृति का उत्पात भी। कभी-कभार थोड़ी देर हल्ला करते हैं। कुछ लोग गरियाते हैं, तो बाकी लोग उसकी वाक्पटुता पर ताली बजाते हैं। बाबाधाम जाना हो तो पेट के बल रेंगते हुए चले जाते हैं। केदारनाथ धाम में बर्फ को झेलते-झेलते पहुंच जाते हैं, लेकिन रोजगार के अधिकार की बात करनी हो, मानवता के अधिकारों की बात करनी हो, तो कुछ संगठित तबकों को छोड़कर, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। खासकर मध्यमवर्गीय तबका, जो अपने स्वार्थ पर तो बाहर निकल आता है लेकिन मारूती के मजदूरों के आंदोलन पर, हकों के लिए उनके गोलियों से भून दिए जाने पर उनका साथ देने के बजाय, हड़ताल का विरोध करता है। लेकिन अभी भी करने के लिए बहुत बाकी है। अपने हित में सोचने वाले लोग क्रांति नहीं ला सकते। व्यक्ति क्रांति नहीं लाते, साधु-संत क्रांति नहीं करते, जमातें क्रांति किया करती हैं। लेकिन भारत के जातितंत्र ने मनुष्य को इतना बांट दिया कि वह जमात बन ही नहीं सका। गुजरात में भूचाल आया तो राहत के लिए लगाए गए कैंपों में सवर्णों ने दलितों को राहत नहीं बांटने दी और दलितों के हाथों से सवर्णों ने राहत नहीं स्वीकार की।

बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है इस देश का इन वर्चस्ववादी सामंती प्रवृत्तियों, बाजारवाद और पूंजीवाद रुझानों से मुक्ति पाने के लिए। ये व्यवस्थाएं व्यक्तिवादी है, समाज हित की नहीं। हमें बदलाव लाने के लिए सामूहिक और संवेदनशील सामाजिक व्यवस्था चाहिए जो समाज की सोचे, समाज हित की नहीं। क्या हमारा लोकतंत्र, जो भीड़तंत्र, जाति-तंत्र, धर्म-मंत्र और क्षेत्र-तंत्र बनकर रह गया है, देश को राहत देने के काबिल है? यह भी सोचने का विषय है। भारतीय लोकतंत्र को कैसे इन उपरोक्त तंत्रों से बचाया जाए, यह एक यक्ष प्रश्न है।

उत्तराखंड से लौटे लोगों के मन में यदि यह बात कौंध जाए कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो शायद वे तर्क करना सीख जाएं और उनका एक मजबूत कदम मनुष्यता की तरफ बढ जाए।

Samples of the Handbill for the forthcomming Rally are being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get these printed and distributed

Confederation Call For A Rally For Reservation In Pvt. Sector And Economic Empowerment

Dr. Udit Raj
National Chairman

On 16th December, 2013 (Monday) at 11 AM, Lakhs of People to Assemble at Jantar-Mantar, New Delhi, And Then To Gherao Parliament

Friends,

The All India Confederation of SC/ST Organizations was established in 1997 to ensure 5 anti-reservation orders issued by the DOPT. Our struggle was so vibrant that one of the rallies held on 11th December, 2000, is reckoned as the biggest rally after Independence. Another feather in the cap of our struggle was mobilization of lakhs of Dalits for conversion to Buddhism on November 4, 2001. When people hardly understood the implication of privatization, the Confederation raised the issue of private sector reservation. In 2006, reservation was given in higher education for OBCs although opposition was so huge and we immediately countered and as a result, it was successfully implemented. When Anna Hazare went on a fast in 2011 and the countrywide mood swung in his favour to bring about one Lok Pal Bill, even at the cost of sovereignty of the Constitution, the Confederation not only replied with matching demonstration but also presented their version of Bahujan Lok Pal Bill. When the Parliament took up this issue for debate, reservation for SC/ST/OBC and minorities in the Lok Pal Bill was considered as envisaged in the Bahujan Lok Pal Bill. Since 1997, the Confederation is the only organization in the country which has struggled and brought forth positive results whereas others have engaged themselves mostly in raising funds, holding seminars, public meetings and conducting cadre camps which are merely a theroretical exercise.

Reservation in private sector is a question of life and death. The UPA I was a little bit serious about it but is now dithering from its stand in UPA II. It is due to our weak support base. Our strength dwindled due to leg-pulling and selfish nature of employees. The Lucknow High Court gave a judgement on 4.1.2011 withdrawing reservation in promotions. We tried to muster the support of the U.P. employees but they refused to come forward and as a result, demand for reservation in promotions could not be fought. In the last paragraph of the judgement, the High Court held that if the State Government wants to continue reservation in promotions, it can do so by complying with the conditions of the M. Nagaraj judgement. In 2006, the Supreme Court gave a judgement in the case of M. Nagaraj, laying down the conditions of backwardness, adequate representation and efficiency. It is to be noted that the 77th, 81st, 82nd and 85th constituitional amendmentls never mentioned such conditions. Unfortunately, the U.P. Government preferred to file a suit in the Supreme Court and the Supreme Court, as it was expected, endorsed the Lucknow High Court verdict on 27.4.2012. The 117th Constitutional amendment which provides reservation in promotion, was passed in Rajya Sabha in last winter session in Parliament and it is yet to be passed by Lok Sabha. All these demands can be met provided our struggle gains the strength.

A Bill to make the Reservation Act is pending in the Parliament since 2004 and till date, it has not been passed. Due to privatization and globalization, social scenario has changed and those who have wealth and black money, control the media and political power. The ideological battle is coming to an end. In such a situation, if SC/ST and OBC people are aloof from economic empowerment, they will be relegated to further backwardness and slavery. For participation in economic empowerment, a strong movement like a political movement has to be launched like training, cadre camp, technological know-how, loans and subsidies facilities, net-working, demand and supply.

Despite the above problems, the exploitation of scavengers is quite acute and it is more due to contract system. There is no reservation in higher judiciary and Army. Geting caste certificate is a big problem and caste certificate of one State is not valid in another State thus depriving job opportunities. Currently we are facing the biggest challenge of Dalit unity and for this, we need to adhere to the ideology of Dr. Ambedkar and other social reformers. Those who are Ambedkarites, are duty bound to mobilize the less Ambedkerite castes like Balmiki, Khatick, Madiga, Passi, Dhanuk, Dhobi and Koli etc. This will not only increase our number but also strengthen us.

Kindly assemble in lakhs at Jantar-Mantar, New Delhi on 16th December, 2013 at 11 AM and thereafter to gherao the Parliament.

By

.

Bhawan Nath Paswan, Dr. Anil Kumar, S.P Singh (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, S.U. Gadpyle, Prakash Patil (M.S.), Maha Singh Bhurania, S.P. Jaravta, Phool Singh Gautam, Deepak Pilot (Haryana), Jasbir Singh Pal, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.-9871237186), Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Lalit Kumar, R. C. Mathuria, Brahm Prakash, A. R. Koli (Delhi), Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), R.V. Singh, Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), D.K. Behera, Dr. K. C. Mallick, Shankhanand, Narayan Charan Das (Orissa), Param Hans Prasad, R.B. Singh (M.P.), R.S. Maurya, Deepak Patel (Gujarat), G. Rangnathan, B. Sagadevan, M. P. Kumar (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, Prem Kumar, I Mysaiah, J. B. Raju, S. Ramkrishna, Y.M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Tarapad Biswas, Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

All India Confederation of SC/ST Organisations
Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42, Telefax: 23354843, Email : dr.uditraj@gmail.com

क्या हमें भविष्य की गुलामी का एहसास है?

डी. हर्षवर्धन

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ''गुलामों को गुलामी का एहसास करवा दो तो वे अपनी गुलामी के खिलाफ बगावत करेंगे।'' बाबा साहेब के इस आदेश का पालन करते हुए इस देश के दलित, आदिवासी, भूमिहीन, खेतिहर मजूदर और महिलाओं में उनकी गुलामी का एहसास करवाकर एक संघर्ष शुरू किया। चूंकि यह संघर्ष अभी तक बिखरा हुआ है इसलिए एक बड़ी सामाजिक क्रांति इस देश में नहीं हो पाई।

आज मैं इस संघर्ष के बिखरने-पनपने की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि हमारा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में गुलामी का एहसास है हमें? यह गुलामी कितनी भयानक है, इसका अंदाजा हमारे प्रस्थापित नेताओं को है क्या?

एक छात्र और युवा नेता होने के नाते मैं वर्तमान स्थिति में इतिहास की जानकारी रखना और अपने तर्कसंगत बुद्धि से भविष्य का अंदाजा लगाने का प्रयास करता रहता हूं। मैं जब इतिहास में झांकता हूं तो दलित, आदिवासियों के ऊपर हुए शोषण और दमन को देखकर थर्रा जाता हूं। इस देश की जाति-व्यवस्था ने लदवाई हुई गुलामी में जी रहे इंसान की जिंदगी नकारी है। इससे बेहतर तो जानवर हैं जो आजादी से जीते हैं। ऐसा लगता है कि इस गुलामी ने इंसान को इंसान होने की सभी शर्त नकारी है। इतिहास के साथ-साथ उसका भयानक जातिवादी स्वरूप भी जानता हूं, वर्तमान स्थिति इससे क्या अलग नहीं है? वही गुलामगिरी आज भी है, दस लाख से भी ज्यादा आज भी दलित मलमूत्र अपने सर पर ढ़ोने को मजबूर हैं। आज भी इस देश का दलित झुग्गी-झोपड़ियों में ही बसा है और दलित ही गंदगी ढ़ोने व इसकी साफ-सफाई का काम करते हैं। आज भी वे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। इस वर्तमान व्यवस्था से उभरने के लिए दलित छात्र-नौजवान संघर्ष कर रहा है। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए छात्र-युवा संघर्षरत् है। छात्र-छात्रा अपनी गरीबी व जातीय शोषण से अपने संघर्ष का अंत देख रहा है। उसे लग रहा है कि कम से कम आरक्षण की बदौलत तो मेरी जाति नहीं मेरी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। यह सोच मेरी नहीं उन संघर्षशील लाखों छात्रों की है, जिन्हें भविष्य में आनेवाली गुलामी का एहसास नहीं है।

भारत में 1999 से भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ। किसी दलित नेता ने उस वक्त यह सवाल नहीं पूछा कि इस दौर में दलितों का क्या स्थान रहेगा? इसी दौरान निजीकरण का दौर शुरू हुआ। देश में निजीकरण का विरोध तो हुआ लेकिन तब तक निजीकरण रोकने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। भूमंडलीकरण और निजीकरण के इस दौर में सरकारी क्षेत्र भी तेजी से निजी होते जा रहे हैं और इसका एहसास भी हमें नहीं हो रहा है। निजीकरण से आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही देश के विभिन्न कार्यालयों में हमारी भागीदारी भी खत्म हो जाएगी। सरकारी स्कूलों का निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इस निजीकरण को रोकने के लिए देश में कोई भी एक जनआंदोलन नहीं खड़ा हो पाया। भागीदारी की बात करें तो वह भी न के बराबर है। आगामी समय में आरक्षण निजीकरण की वजह से खत्म हो जाएगा जिससे हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। ऐसे हालात में हम फिर से वही गुलामी की स्थिति में आ जाएंगे। जिस गुलामी में हमें न तो आरक्षण के माध्यम से अवसर दिया जाएगा न ही अच्छी शिक्षा। फिर से निचले दर्जे के काम से हमें दो-चार होना पड़ेगा। इससे न तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेंगी, न हमें समाज में इज्जत मिलेंगी, न इस स्थिति से उभरने के ख्वाब देखने के लायक रहेंगे और न ही संघर्ष करने के लायक। वर्तमान में छात्र व नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए सामाजिक आंदोलन से दूर हैं। ये दूरियां युवकों को अपने भविष्य और आने वाली नस्ल को गुलामी की ओर धकेल रहा है।

नेशनल एससी/एसटी/ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट हमारे भविष्य के लिए देश में दलित, आदिवासी व ओबीसी की भागीदारी की मांग को लेकर कार्य कर रहा है। पिछले 15 सालों से डॉ. उदित राज हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के माध्यम से इस आंदोलन को संघर्षशील बनाए रखे हैं।

मुझे इतिहास मालूम है, वर्तमान स्थिति में जी रहा हूं और भविष्य की गुलामी का एहसास हो रहा है। इसलिए मैं आज जाग उठा हूं। इस गुलामी के खिलाफ मैंने आवाज उठाया है। आज भविष्य को सुरक्षित करने के लिए छात्र व युवाओं को जागरूक कर रहा हूं। अगर इस देश के दलित, आदिवासी व ओबीसी छात्र और युवाओं को आनेवाली गुलामी का एहसास हुआ है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण के आंदोलन में शामिल हों होकर संघर्ष करो।

आरक्षण नहीं हिस्सेदारी है

एस. एल. सागर

हम बराबर चर्चा करते आ रहे हैं कि आरक्षण विभिन्न वस्तुओं के अलग-अलग अधिकार का हो सकता है किन्तु एक ही वस्तु को विभाजित करना आरक्षण नहीं हिस्सेदारी होती है। संविधान में विधायिका के साथ जो नौकरियां अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अलग उनकी आबादी के अनुपात में बंटवारा किया गया है वह वास्तव में आरक्षण नहीं हिस्सेदारी है। इस व्यवस्था में यह एक ही विधा का अलग-अलग हिस्सों में बंटवारा है। यदि एक जाति के लिए विधायिका में, दूसरी जाति के लिए केवल नौकरी में, तीसरी जाति को व्यापार में तथा चौथी जाति को केवल कारीगरी के व्यवसाय में सीमित किया जाता है तो यह जाति आधारित आरक्षण होता। दूसरी ओर यदि विधायिका में 20 सदस्य एक जाति के लिए और 80 सदस्य दूसरी जाति के लिए निश्चित किए जाएं तो यह विधायिका में 100 सदस्यों का बंटवारा जाति के आधार पर 1 और 4 भाग का होगा। वर्तमान में विधायिका और नौकरियों में जो अनुसूचित जाति/जनजाति को आबादी के अनुपात में स्थान दिए जाने की व्यवस्था की गई है वह हिस्सेदारी है आरक्षण नहीं। दरअसल आज देशभर में जो दलितों और पिछड़ों को हिस्सेदारी हमारे संविधान ने दी है उसके विरूद्ध हो-हल्ला है। उसका कारण उन वर्गो की अनैतिकता ही प्रतीत होती है जो हजारों वर्षो से आरक्षण का लाभ उठाते आ रहे हैं और दलित-पिछड़ों का हिस्सा खाते आ रहे हैं। वे दूसरों का हिस्सा उन्हें नहीं देना चाहते और स्वंय उस पर डकैती डाले रहना चाहते हैं। ये सरासर बेईमानी कर रहे हैं और कभी विशेष व्यवस्था कहकर, कभी समानता विरोधी कहकर और कभी सत्ता अयोग्यों के हाथ में देकर राष्ट्र का अहित करने जैसे आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि हजारों वर्षो से ये स्वंय दूसरों के हक पर नागों की तरह कुंडली मारे बैठे हैं। वे किस न्याय नीति के आधार पर दूसरों का हक खाते रहे हैं तब तो उन्होंने स्वयं अपने लिए विद्या, बल और धन का आरक्षण कर रखा था। दरअसल उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि विद्या-ज्ञान ब्राह्मणों के लिए, बल और सत्ता क्षत्रियों के लिए तथा उद्योग धंधा, व्यापार, धन अर्जन वैश्यों के लिए आरक्षित कर रखे थे।

आरक्षण और हिस्सेदारी अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। आरक्षण स्वंय में अप्रिय और विवादित व्यवस्था है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि आरक्षण और हिस्सेदारी को स्पष्ट समझना चाहिए था। एक नहीं अलग-अलग दो व्यवस्थाएं हैं। एक मद (वस्तु) जब एक व्यक्ति को समर्पित की जाय तो यह आरक्षण का विषय है और जब एक मद या वस्तु को विभाजित कर एक से अधिक व्यक्तियों में विभाजित की जाय तो वह क्रिया हिस्सेदारी है। आरक्षण समानता विरोधी व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था एक असंगत व्यवस्था है जब एक कार्य या वस्तु एक व्यक्ति या एक वर्ग के नाम अधिकृत हो जिसमें दूसरे का कोई हक न हो तो यह आरक्षण व्यवस्था है और यह आरक्षण व्यवस्था नैसर्गिक समतारोधी व्यवस्था है। हिस्सेदारी एक आवश्यकता की उपज है। आरक्षण व्यवस्था छल, बल और प्रपंच पर टिकी होती है। हिस्सेदारी आरक्षण विरोधी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में हर मद या वस्तु में बंटवारा हिस्सेदारी की व्यवस्था है। वर्ण-व्यवस्था के आधार पर जो व्यवस्था कार्य विभाजन की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए भी मद थी। इस व्यवस्था में एक के कार्य में दूसरे वर्ग की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा एक ही कार्य या मद में विभिन्न सामाजिक गुणों में जो बंटवारे की व्यवस्था की है वह हिस्सेदारी है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए नौकरियों में उनकी आजादी के बराबर विभाजन आरक्षण नहीं हिस्सेदारी है।

अपने लिए द्विजों ने भारत में आरक्षण की व्यवस्था हजारों वर्ष पहले की थी। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के लिए हिस्सेदारी की व्यवस्था स्वतंत्रता बाद वाले संविधान द्वारा की गई है। आज भारत में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है। पहली व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था है। दूसरे प्रकार की नवीन व्यवस्था संवैधानिक है। पहली व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और दूसरी संवैधानिक व्यवस्था पर। पहली व्यवस्था में जब वर्ण-व्यवस्था ने अपना रूप धारण किया तो दान देना-लेना, यज्ञ करना-कराना एवं अन्य यानि की कुल मिलाकर छह कर्म/अधिकार ब्राह्मण वर्ण ने अपने नाम आरक्षित कर लिए। क्षत्रीय वर्ण के नाम दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ना, राज्य करना और रक्षा करने का आरक्षण कर दिया गया। वैश्य वर्ण के नाम कृषि और व्यापार तथा शूद्र के नाम सेवा कर्म आरक्षित कर दिया गया। यह आरक्षण व्यवस्था पिछले हजारों वर्षो से चली आ रही है। यह आरक्षण इतने कड़े प्रतिबद्धताओं के साथ लागू रहा कि यदि किसी व्यक्ति ने इसका उल्लंघन किया तो ऊपर के तीन वर्णो का जातिच्युत कर दिया जाता था जबकि शूद्र वर्ण के हाथ-पैर और जिह्वा तक काट लिए जाते थे और किसी धर्म ग्रंथ के वाक्य (श्लोक) सुन लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। यदि कोई शूद्र धन कमा लेता था तो द्विज उससे यज्ञ कर्म के लिए छीन लेता था।

दूसरे प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था पुराने आरक्षण के कारण ही करनी पड़ी थी जिसमें शूद्रों को हिस्सेदारी दी गई। ढ़ाई-तीन हजार वर्ष से शूद्र वर्ण के नाम से आज के दलित एवं पिछड़ों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिणक सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। उन दलित-पिछड़े शूद्रों को धन कमाने की मनाही थी, पढ़ने की मनाही थी। समाज में ये अछूत और शूद्र थे। ये राज-काज से कोई संबंध नहीं रख सकते थे। वर्ण-व्यवस्था पर आधारित आरक्षण ने ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता और क्षत्रीय को राजा के रूप में भगवान का अवतार, वैश्य को लक्ष्मी और शूद्र को जिसकी आबादी कुल की तीन चौथाई थी, ऊपर के तीनों वर्णो का सेवक बनाकर दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया।

Rahul Gandhi Should Do What Mayawati Has Not Done

Dr. Udit Raj

Rahul Gandhi Ji said on October 8, 2013 at Talkatora Stadium that Ms Mayawati does not allow any Dalit leader to come up which is a fact. This shows that Rahul Gandhi is concerned with the welfare of Dalits. In reality, there is a vacuum in Dalit leadership. As compared to upper caste and Backward leaders, the number of Dalit leaders is very negligible. During any rally of Bhartiya Janata Party, we do see prominent upper caste leaders of the party like L.K. Advani, Sushma Swaraj, Arun Jaitley, Nitin Gadkari, Narendra Modi, Murli Manohar Joshi etc. on the dais but there are no Dalit leaders. Similarly on the Congress platforms, Dalit leaders are hardly to be seen and if once in a while they are to be seen, it is only those Dalit leaders who are sponsored by the party rather than those who are Dalit leaders in their own right because of society support. Besides the parties, Media also plays a significant role in making leaders. When in the year 2010, Anna Hazare launched a march against corruption from Gandhi Samadhi to Jantar Mantar, there were less than 100 people with him. When the Media projected him in the year 2011, he did not only come to limelight at the national level but at the international level also. India is essentially a caste ridden country and unless all the castes have participation in the governance of the country, the country will remain backward and development will always be tardy. A leader creates awareness among people of his caste and there is a great need to create such awareness among Dalits because they are still at a very low ebb in the social hierarchy. When Dalits become prosperous, there will be overall development in the country.

Existence of a leader can be made or destroyed. Despite the best efforts of a party or leadership, a Dalit leader may not emerge on his own.If the intention is not to allow a Dalit leader to come up, then it is not possible to create a big Dalit leader.The real question is whether there is a big Dalit leader in the Congress? The answer is that in the Congress Party also, there is only a middle level Dalit leaders and those who are projected as national level it is the handwork of of party . Why has the Congress Party not made any effort to create a national level Dalit leader? Even if the Congress Party wants to do so, they cannot do it because at present they do not have any Dalit leader who can be groomed to become a national Dalit leader. Of course, party and media play an important role in grooming a national level leader but such a person must also have the capacity and capability to become a national level leader. Patronage and family background have their own limitations. A leader is a product of struggle. Knowledge and ability are the basic requirements. When these qualities are existing in a person, patronage and family background are also helpful in grooming a national level leader. Both the BJP and the Congress Party, at present, just do not have such a Dalit leaders and much as they would like to have such a person, the possibility is remote.

If we analyze in detail, we shall find that Mayawati is more a product of circumstances. When Kanshi Ram Ji launched his campaign to mobilize Dalits, then it was like a green field scenario and Dalits were desperately looking for a leader. BAMSEF and Bahujan Samaj Party had leaders who were more senior and capable than Mayawati but Kanshi Ram gave her a chance to come up. She had the special blessings of Kanshi Ram and it is because of this reason that most of her contemporaries left BAMSEF and BSP. BSP has been fiercely making a false propaganda against me by projecting that I am an agent of the Congress Party or the BJP. Dalits were misled to believe that I have been created to weaken Ms Mayawati. A person becomes an agent mainly for two reasons: money and power. I kicked the job of an Additional Commissioner of Income Tax, a money-spinning position, and had I got any power or position, it would have been visible to one and all. What Rahul Gandhi has said in this regard, I have been saying the same thing in a different manner at my rallies and meetings. Very often I have been asking if anybody in BSP has got the courage to arrange an appointment for me with Ms Mayawati or talk about me with her. I want to meet her for two reasons, one, that for the last 15 years, one-third of reservation is finished and why she is not protesting against this? On the issues of price-rise and corruption, no agitations etc are organized. Reservation Bill has been lying pending in the Parliament since 2004. Why is she silent on this issue? How was reservation in promotions abolished in Uttar Pradesh during her tenure? Why is she not allowing her own party leaders to express their views freely on these issues and take a majority decision? Can she bring about empowerment of Dalits by this autocratic rule? There are about forty BSP MPs in Lok Sabha and Rajya Sabha put together. Why does she not give them the freedom to speak, protest and struggle whenever rights of Dalits are violated, or whenever there are atrocities against Dalits? Atrocities and discrimination against Dalit employees and officers are happening frequently. Why are BSP MPs and leaders not allowed to meet concerned officers and Ministers to quell the grievances. It is these employees and officers who were responsible for creating BAMSEF, Kanshi Ram and Mayawati. Why then these people are being kept at a distance? Even other parties are not doing like that. Most of the Dalits are supporting Mayawati not because of her achievements but because she is the only big icon and they want to hold on to her. An average Dalit considers that an upper caste or a backward leader will also not do anything significant for them and so at least for psychological satisfaction, social status and respect, they do not withdraw their support to her even though they are not getting any substantial gains. However, if Mayawati does not change her attitude, the day is not far when she will be left with a very small number of supporters. This amounts to nothing but exploitation of the sentiments. BSP is not having even three-four Dalit leaders in the whole of the country who are of the stature of Satish Mishra, Shashank Shekhar, Swami Prasad Maurya and Nasimuddin Siddiqui? Why in her meetings, no Dalit leader sits on the dais? She even goes to the extent that no Dalit leader should come up in the party with which she is herself associated. The main purpose for my seeking meeting with her is to tell her about these issues and if she is ready to change her attitude, we could take upon ourselves the task of consolidating all Dalits under one banner. We could hold discussions with Ram Vilas Paswan and Ram Das Athavale and others also. I know that it may not happen at present because of her arrogant attitude.

At this point of time, I would also like to make a mention about Ashish Nandi when he said that in Bengal, no Dalit leader has come up in the last 100 years. The State has been under the Communist rule for nearly 35 years. Why has no Dalit leader come up? It is surprising because leaders of Communist parties emerge from the working class. Dalits, Adivasis and Most Bakcwards are really from working class. I was born in a village in a very ordinary family. I plunged into social and political work after kicking a very senior job in the Government of India. I have been meeting Rahul Gandhi and sometimes there have been exchange of views also. I do not believe in caste politics. In today's context, it is not possible to do politics without black money. As such it will take a long time for me to come up in politics. I have also not got Media support as is the case with Arvind Kejriwal. Because of the Media hype, he got workers, organization and means all put together. I did not get any such advantage, but despite this, I have got a powerful social organization. Dalits, Adivasis, Backwards and the downtrodden are behind me and have confidence in me. If Rahul Gandhi Ji so desires, he may help me in coming up which in turn will help in accomplishing his desire to create Dalit leadership. I have got ample experience of administration and economic issues. I am not indulging in self-praise but I can challenge that no Dalit leader can beat me in organizational capability, struggle and knowledge. It is worth seeing as to how Rahul Gandhi responds to my suggestion.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 23 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 October, 2013

Why Did The Caravan Flop?

Dr. Udit Raj

During 1970-decade, Kanshi Ram and his compatriots started awareness campaign in Maharashtra which gradually reached North India. It was the need of the hour to explain the history of Aryans and Non-Aryans as also to challenge the evil designs of the Hinduism. Provocative slogans like Tilak, Tarazoo and Talwar maro Inko Juta Char etc were coined. It had become imperative to put across the ideas of social justice propounded by great men before the common people for inspiring them. This approach had a positive impact in as much as it did not only create awareness among Dalits but also inspired them to put up a united struggle for a share in governance. A non-religious ,a non agitational and a non-political movement was built to prepare Bahujans psychologically for their pride and dignity. It has little semblance with the ideology of Dr. Ambedkar to educate, to unite and to struggle. Dr. Ambedkar talked of capturing political power whereas this campaign was non-political at the preparatory level. He had talked of bringing about social change through Buddhism whereas this campaign was non-religious. This was a well-planned strategy to motivate the people. When people had been suitably motivated, then Kanshi Ram gave it a practical shape which resulted in the formation of Bahujan Samaj Party. Those who did not agree to convert it in to political outfits, followed parrot policy to go on repeating the same. They should diverted the movement to bring about change in the areas of education and religion. Theoretical preparation is inevitable but after that practice has to be followed. To organize cadre camps, telling the stories of exploitation, charge the workers emotionally , to collect subscriptions and to set up objectives and goals become the order of the day and completely bereft of struggle, issues and creation of an alternative culture to Brahmanism. They failed to see the dangers like liberalization and privatization started in the time of the former Prime Minister Narasimha Rao. This marks the beginning of the end of reservation and Dalit organizations kept on adhering to the old pattern of movement. The situation can very well be compared to the time when Rome was burning and Niro was playing his flute.

Bahujan Samaj Party has, of course, made some political gains which gave psychological strength but major issues concerning Dalits like share in governance, economic empowerment, day to day atrocities, acute exploitation of Safai karamachari and reservation in pvt. sector which is the basis for empowerment have not been resolved. When the BJP-led Government came to power at the Centre, reservation started getting further eroded because of the policy of disinvestment. For example, at one time, there were 7 lakh employees in Coal India but now the number has been reduced to about 3.5 lakhs. Outsourcing, disinvestment of Government departments and Public Sector Undertakings and their outright sale have further eroded the reservation stretch. Under these circumstances, what are our people and organizations doing? The community should ask these organizations as to why even after getting votes and notes and all other kinds of support, the caravan has flopped? Where were these people when 5 anti-reservation orders were issued in 1977? Privatization could not be stopped even by a powerful country like Russia and China in the process of stoppage, the onslaught of privatization, the country got fragmented. Similarly we also cannot stop the process of privatization but can have employment quote and other benefits like in US and Europe. It is because of Confederation that the issue of reservation in the private sector has gained momentum but so far we have not achieved this right. We furthered the cause of Buddhism with a view to establish casteless society.Where were these people then? And now also they are not likely to do anything. The manner in which Anna Hazare and his people wanted the Lokpal Bill to be passed would have passed the power again to the hands of the upper caste people. Anna Hazare and his people had sought power for Lokpal to launch enquiries under the Lokpal Bill against Parliament proceedings, Prime Minister, CBI and Judiciary etc. and had it been adopted like that, could Dalits, Adivasi and Backward leaders raise their voice fearlessly ? They would have been implicated and put behind the bars even in false cases. It is the Confederation which had placed Bahujan Lokpal Bill before the Parliamentary Standing Committee and as soon as discussion on the Bill started on the floor of the House, the issue of reservation was immediately accepted. Whenever the Lokpal Committee is constituted, it will have to reflect the participation of SC/ST and Backward people. On the one hand, reservation is being gradually abolished, on the other, there is privatization of education. Thousands of Colleges and Universities and Institutions for Engineering, Management, BBA and Medicine have been opened in the country in the recent past. What have these so-called missionaries and Ambedkarites have done in this regard?

Because of reservation in government and educational institutions, Dalits have not only achieved economic independence but have gained self-respect and made progress in various fields. Even now this community does not have any other option except reservation just as business is a power tool in the hands of Vaishyas. Kshatriyas are not only having a sizeable share in the administration but also own properties. So far as Brahmins are concerned, they have got 100% reservation in the management of temple economy besides their share in education and administration, which is quite high, is already there. Among Backwards also, people of some castes have landed properties and business avenues. Despite so many welfare schemes and plans, still reservation is the only main source of survival for Dalits and Adivasis. Condition of most backwards and backward Muslims is equally deplorable and unfortunately they are not coming forward to struggle for their share in governance.

For the last fifteen years, the All India Confederation of SC/ST Organizations has not only launched a struggle on principles but it has delivered results also. It is because of the struggle of the Confederation that the five anti-reservation orders issued in 1997 were withdrawn. Had the 81st, 82nd and 85th Constitution Amendments not been passed,anti- reservation orders were sufficient to abolish reservation. A great ideological revolution took place on 4.11.2001 when lakhs of Dalits were converted to Buddhism. Struggle for reservation in private sector has been going on for the last so many years and on the 16th December, 2013, like the previous years, a huge rally is being organized in Delhi. We have given to our community much in terms of social change and their rights as compared to the cooperation and support which we got from the community and we promise to continue this caravan. It is unfortunate that the community has not understood the importance of our movement properly and have instead taken sides with people who have not taken any responsibility and expressed only lip sympathy and sold the dreams.

Change in Date & Venue of Confederation Rally

Due to a change in the date of the Winter Session of the Parliament which was to be held earlier on 25 November, the Rally of the Confederation will now be held on 16 December. The Venue of the Rally has also been changed from Ramlila Maidan to Jantar-Mantar, New Delhi.

- Dr. Udit Raj
(National Chairman)

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn